



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

भारतीय विदेश नीति: बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका

डॉ. संजय भारद्वाज

सह आचार्य

राजकीय महाविद्यालय, परबतसर, डीडवाना कुचामन (राज.)

संक्षेप

भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुई है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलन बदल रहा है, तो दूसरी ओर भारत एक उदयमान शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है। भारत ने परंपरागत गुटनिरपेक्षता की विरासत से आगे बढ़कर "रणनीतिक स्वायत्तता" का मार्ग अपनाया है, जिसका अर्थ है भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र रुख बनाए रखेगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, बहुपक्षीय मंचों का बदलता स्वरूप, और उभरती चुनौतियाँ जैसे ऊर्जा सुरक्षा व डिजिटल परिवर्तन शामिल हैं – में भारत संतुलित एवं बहुआयामी विदेश नीति पर चल रहा है। नीचे विभिन्न समकालीन घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत की भूमिका और रणनीति का विश्लेषण किया गया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध: तटस्थता और रणनीतिक संतुलन

फरवरी 2022 में आरंभ हुए रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत ने एक निरपेक्ष एवं संतुलित रुख अपनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में रूस की सीधी निंदा से परहेज़ करते हुए युद्ध तुरंत रोकने और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन संकट पर भारत की नीति स्थिर और सतत है। भारत बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करता है, संघर्षविराम की तत्काल आवश्यकता बताता है तथा सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का आह्वान करता है। भारत ने इस युद्ध से उपजी मानवीय चुनौती को भी ध्यान में रखकर यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को मानवीय सहायता पहुंचाई।¹

भारत का यह तटस्थ रुख "रणनीतिक संतुलन" का परिचायक है। उसने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखा है, वहीं युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में यहां तक कहा कि "आज का युग युद्ध का युग नहीं है", संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाने पर बल दिया। इस संतुलित दृष्टिकोण के पीछे कई कारण हैं: रूस भारत का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार रहा है, विशेषकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में, तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंचों पर भी रूस ने भारत का साथ दिया है। दूसरी तरफ, यूरोप तथा अमेरिका के साथ भी भारत के घनिष्ठ आर्थिक और सामरिक संबंध हैं। अतः भारत किसी एक खेमे में शामिल हुए बिना दोनों ओर से अपने हितों की रक्षा कर रहा है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

इसे कुछ विश्लेषक भारत की नई “बहु-संरेखण” नीति भी कहते हैं, जहाँ भारत अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग साझेदारियों में लिप्त है।

इस रणनीति का व्यावहारिक पहलू ऊर्जा सुरक्षा में दिखा है – पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रियायती दरों पर रूस से तेल आयात बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप 2023 तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जो भारत की कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 36 प्रतिशत था (लगभग 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन)।ⁱⁱ इससे भारत को सस्ते ऊर्जा स्रोत मिले और घरेलू महंगाई नियंत्रित रखने में मदद मिली। हालाँकि इस संतुलनकारी नीति के चलते कुछ पश्चिमी देशों ने असंतोष जताया, भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय हितों को साधना है। कुल मिलाकर, रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ लेकिन सैद्धांतिक रुख अपनाकर शांतिवार्ता, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय सहायता को प्राथमिकता दी, और अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने का प्रयास किया।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व निकटता आई है। शीतयुद्ध के बाद के दशकों में अविश्वास को पीछे छोड़ते हुए दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी कायम की है, जो आज रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक हो चुकी है। विशेषकर पिछले एक दशक में रक्षा सहयोग तेज़ी से बढ़ा है। 2016 में अमेरिका ने भारत को “मेजर डिफेंस पार्टनर” का दर्जा दिया, जिससे भारत को उन्नत रक्षा तकनीक की प्राप्ति का मार्ग खुला। इसके पश्चात् तीनों आधारभूत रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए: 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिन्क्रोरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)। इन समझौतों ने भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक सैन्य संचार उपकरण और भू-स्थानिक जानकारी साझा करने की सुविधा दी, जिससे भारतीय सेना की तकनीकी क्षमताओं में इज़ाफ़ा हुआ। 2018 के उद्घाटन 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद के संयुक्त बयान में COMCASA के हस्ताक्षर का स्वागत किया गया, क्योंकि इससे भारत को अमेरिकी रक्षा प्रणालियों का पूर्ण लाभ उठाने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच रीयल-टाइम सूचना आदान-प्रदान का रास्ता खुला।ⁱⁱⁱ

द्विपक्षीय रक्षा व्यापार भी लगभग शून्य से बढ़कर 20 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, जिसमें भारत ने अमेरिका से परिवहन विमानों, समुद्री निगरानी विमानों, हमला हेलिकॉप्टरों आदि की खरीदारी की है। समान हितों के चलते दोनों देशों की सेनाएँ नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास (मालाबार नौसैनिक अभ्यास सहित) कर रही हैं। 2022 में दोनों देशों ने नए उभरते रक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए इनीशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नॉलजीज (iCET) नामक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G/6G, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आदि में मिलकर काम करना है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका राजकीय यात्रा ने इस साझेदारी को एक नई ऊँचाई दी। वॉशिंगटन डी.सी. में दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के ऐतिहासिक समझौते किए, जिनमें प्रमुख हैं – भारत में जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से लड़ाकू विमान इंजन निर्माण



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

का समझौता तथा भारतीय सेना के लिए MQ-9B सीगार्जियन सशस्त्र ड्रोन की खरीद।^{iv} संयुक्त बयान में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन द्वारा गुजरात में \$2.7 अरब मूल्य का अर्धचालक परीक्षण एवं पैकेजिंग संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी आपूर्ति-श्रृंखला सहयोग का हिस्सा है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों के लिए भारतीय शिपयार्ड में मरम्मत सुविधा संबंधी समझौते से हिंद-प्रशांत में आपसी सैन्य लॉजिस्टिक्स सहयोग को बढ़ावा मिला।^v

भारत-चीन संबंध और सीमावर्ती तनाव

भारत और चीन के संबंध सहयोग और तनाव दोनों से बने हैं। व्यापार, बहुपक्षीय मंचों और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों में सहयोग होता है, लेकिन सीमा विवाद इन रिश्तों में लगातार तनाव पैदा करता है। जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद यह तनाव कई गुना बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों की मौत हुई और दशकों बाद पहली बार इतनी गंभीर मुठभेड़ देखने को मिली। इसके बाद दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी सैन्य तैनाती कर दी, और कई दौर की बातचीत के बावजूद देपसांग और डेमचोक जैसे सेक्टरों में स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो पाई है। गलवान के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर शांति बहाल हुए बिना द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसी कारण भारत ने सीमा अवसंरचना को तेजी से विकसित किया, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और चीनी कंपनियों के निवेश की कड़ी समीक्षा शुरू की। राजनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत काफी कम हो गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत ने अपने रुख को और सख्त कर लिया है।

हालाँकि तनाव बढ़ने के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार नई ऊँचाइयों पर पहुँचा है। 2022 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचा, लेकिन इसमें भारत का व्यापार घाटा बेहद बढ़ा रहा। इससे भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता का एहसास हुआ। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है और क्वाड का सक्रिय सदस्य है, जबकि चीन की आक्रामक गतिविधियाँ और पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ रिश्ते भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके बावजूद दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर बातचीत और सहयोग जारी रखते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सीमा विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, आपसी विश्वास की बहाली मुश्किल बनी रहेगी।^{vi}

बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका: ब्रिक्स, क्वाड, G20

भारत बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन के बीच बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सक्रियता और प्रभाव को निरंतर बढ़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करना और एक अधिक न्यायसंगत व बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण—ये सभी भारत की विदेश नीति के केंद्र में हैं।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

इन उद्देश्यों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति ब्रिक्स, क्वाड और G20 जैसे प्रमुख बहुपक्षीय समूहों में भारत की भूमिका से होती है।

ब्रिक्स – ब्रिक्स में भारत संस्थापक सदस्य है और इसे वह पश्चिम–प्रधान वैश्विक आर्थिक ढांचे के विकल्प के रूप में देखता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक मुद्रा व्यवस्था जैसी पहलों में भारत की भागीदारी इसकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है। 2023 में ब्रिक्स विस्तार के दौरान भारत ने सावधानीपूर्ण और संतुलित रुख अपनाया।^{vii} जहाँ चीन और रूस बड़े पैमाने पर विस्तार चाहते थे, वहीं भारत ने सुनिश्चित किया कि विस्तार के बाद भी ब्रिक्स किसी पश्चिम–विरोधी गठजोड़ के रूप में न उभरे। भारत का लक्ष्य है कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के आर्थिक मुद्दों, वैश्विक शासन सुधार और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूती देने जैसे रचनात्मक एजेंडे पर केंद्रित रहे। इसी कारण भारत ने यूक्रेन संकट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तटस्थ और संतुलित भाषा पर जोर दिया, जिससे संगठन के भीतर एकता बनी रहे।^{viii}

क्वाड – क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रभावी रणनीतिक मंच है, जिसका उद्देश्य हिंद–प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और नियम–आधारित बनाए रखना है। हाल के वर्षों में क्वाड की गतिविधियाँ काफी बढ़ी हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान क्वाड देशों ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण में बड़े स्तर पर सहयोग किया। इसके अलावा, क्वाड ने उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला मजबूती और समुद्री सुरक्षा के लिए कई कार्य–समूह बनाए हैं। भारत के लिए क्वाड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे समान विचारधारा वाले प्रमुख देशों के साथ मिलकर चीन की आक्रामक नीतियों का संतुलन बनाने में मदद करता है। क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन मालाबार नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से इसका रक्षा सहयोग लगातार सु–ढ हो रहा है।^{ix}

G20 – G20 में भारत की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में और अधिक प्रभावशाली होकर उभरी है। 2023 में भारत की अध्यक्षता ऐतिहासिक रही। “वसुधैव कुटुंबकम्” की थीम के अंतर्गत भारत ने समावेशिता, वैश्विक एकजुटता और सतत विकास पर विशेष बल दिया। न्यू दिल्ली शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना थी, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिला। यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अत्यंत संतुलित भाषा सुनिश्चित की मानवीय पीड़ा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता जताई, पर किसी देश पर सीधे आरोप लगाने से बचते हुए शांति की अपील की। यह एक कठिन संतुलन था, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक साधा।^x

इसके अलावा, G20 के एजेंडे में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, हरित विकास कॉम्पैक्ट, मिशन लाइफ (सतत जीवनशैली) और विकासशील देशों के लिए ऋण राहत जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। इससे G20 अधिक समावेशी बना और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को नई पहचान मिली। भारत अन्य बहुपक्षीय मंचों में भी सक्रिय रहा है—संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास, आतंकवाद–रोधी पहलों में नेतृत्व, आसियान मंच और शंघाई सहयोग संगठन में सहभागिता—ये सभी उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाते हैं।

दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीति: पड़ोसी प्रथम नीति

Volume 1, Issue 9, September 2025

Website: kavyasetu.com



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

भारत अपनी विदेश नीति में दक्षिण एशिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, क्योंकि अपने निकटवर्ती पड़ोस को शांत, स्थिर और समृद्ध बनाए रखना उसकी सामरिक व आर्थिक आवश्यकता है। इसी सोच से “नेबरहुड फ़र्स्ट” नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता, आपदा राहत, कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और क्षमता निर्माण में प्राथमिकता देता है। भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण-रेखाएँ, अनुदान, अवसंरचना परियोजनाएँ और तकनीकी प्रशिक्षण इस दृष्टिकोण की आधारशिला हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न पड़ोसी देशों में भारत की सक्रिय कूटनीति इसके ठोस उदाहरण प्रस्तुत करती है।

श्रीलंका के गंभीर आर्थिक संकट (2019–22) के दौरान भारत ने सबसे बड़ा सहयोगी बनकर सहायता प्रदान की। विदेशी मुद्रा भंडार घटने से जब श्रीलंका में ईंधन, भोजन और दवाओं की भारी कमी हो गई, तब 2022 में भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर मूल्य की सहायता—ऋणरेखाएँ, स्वैप सुविधा, मानवीय मदद और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति—उपलब्ध कराई। इस सहायता में ईंधन खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट, चिकित्सा आपूर्ति और भारतीय नौसेना द्वारा भेजे गए राहत सामग्री शामिल थे। यह मदद न केवल मानवीय संकट को कम करने में सहायक बनी, बल्कि भारत द्वारा “पड़ोसी प्रथम” सिद्धांत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी दर्शाती है।^{xi}

नेपाल के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक साझेदारी पर आधारित हैं। हालिया वर्षों में कुछ विवादों के बावजूद द्विपक्षीय संबंध फिर से मजबूत हुए हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री ‘प्रचंड’ की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें सबसे प्रमुख 10,000 मेगावाट बिजली आयात का पावर ट्रेड समझौता है, जो नेपाल की जलविद्युत क्षमता को आर्थिक अवसरों में बदलने और भारत की स्वच्छ ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों देशों ने पारगमन संधि में सुधार किया, जिससे नेपाली सामान की आवाजाही भारतीय बंदरगाहों तक सरल हुई। इसके अतिरिक्त, UPI—रुपे और भीम—नेपाली भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर सहमति बनी, जिससे पर्यटन और व्यापार को नया प्रोत्साहन मिला।^{xii}

भूटान भारत का सबसे घनिष्ठ पड़ोसी है। जलविद्युत सहयोग दोनों देशों के रिश्तों की आधारशिला है। भारत ने भूटान में कई प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण और वित्तपोषण किया है। नवंबर 2025 में 1020 मेगावाट पुनात्संगचू-II परियोजना का उद्घाटन भारत की सहायता से हुआ, साथ ही भारत ने नई परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपये की रियायती ऋण सुविधा भी दी। इससे भूटान की ऊर्जा क्षमता में 30–40 प्रतिशत तक वृद्धि की उम्मीद है। भूटान के शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और आधारभूत ढाँचे में भी भारत लगातार सहायता करता है। सुरक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी अत्यंत मजबूत है, और भारत भूटान की सेना को प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराता है। क्योंकि भूटान चीन सीमा विवाद के बीच रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति में है, भारत वहाँ के राजनीतिक विकास पर विशेष ध्यान देता है।^{xiii}

बांग्लादेश और मालदीव भारत की “नेबरहुड फ़र्स्ट” नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते (2015) के बाद संबंध नए स्तर पर पहुँचे—ऊर्जा व्यापार, रेल-सड़क कनेक्टिविटी, रक्षा सहयोग



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

और बढ़ता व्यापार इसका प्रमाण हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मालदीव में भी भारत प्रमुख विकास भागीदार है; पेयजल संकट से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, भारत ने समय-समय पर मालदीव की सहायता की है। पुल निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और रक्षा प्रशिक्षण जैसी परियोजनाओं ने दोनों देशों की निकटता को और बढ़ाया है।

पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों से अत्यंत निचले स्तर पर हैं। सीमा-पार आतंकवाद के कारण भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते।" पुलवामा हमले (2019) के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुँच गया। यद्यपि मानवीय मामलों—जैसे मछुआरों की रिहाई या तीर्थयात्रा पर सीमित संवाद जारी है, परंतु व्यापक संबंध लगभग ठप हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट भी संबंधों में सुधार की संभावनाओं को कमजोर करते हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान के 2021 के पुनः नियंत्रण के बाद भारत की निवेश और विकास परियोजनाएँ प्रभावित हुईं। फिर भी भारत ने अफगान जनता के प्रति अपना समर्थन जारी रखा और 2022–23 में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता—गेहूँ, दवाइयों, कोविड—वैक्सीन भेजीं। भारत ने तालिबान से सीमित व्यावहारिक संपर्क भी बनाए रखा ताकि सहायता वितरण की निगरानी हो सके। 2023 में भारत ने काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति धीरे-धीरे पुनः स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए, इस उम्मीद के साथ कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद के लिए न हो और देश में समावेशी शासन विकसित हो।^{xiv}

समग्र रूप से, दक्षिण एशिया में भारत स्वयं को "नेट सुरक्षा प्रदाता" और सबसे विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह नीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा के समय त्वरित सहायता, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, लोगों के बीच संपर्क और मानवीय समर्थन के वास्तविक कदमों में साकार होती है। पड़ोस के स्थायित्व और विकास को सुनिश्चित करके भारत अपने व्यापक वैश्विक लक्ष्यों को और मजबूती से आगे बढ़ा पाता है।

विदेशी पहल: 'एक्ट ईस्ट', 'नेबरहुड फ़र्स्ट', 'सागर'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को नई दिशा और सक्रियता मिली है, जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फ़र्स्ट, और सागर (SAGAR) जैसी पहलें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारत की पारंपरिक नीतियों को अद्यतन करते हुए देश की क्षेत्रीय और समुद्री भूमिका को सुदृढ़ बनाना है, ताकि भारत एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रभावी, विश्वसनीय और संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरे।

एक्ट ईस्ट नीति 1990 के दशक की "लुक ईस्ट" नीति का उन्नत और सक्रिय संस्करण है, जिसे 2014 में विशेष रूप से गति प्रदान की गई। इसका लक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशिया और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। आसियान इस नीति का केंद्र है, और भारत ने इसके साथ अपने संबंधों को संवाद भागीदार से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत ने व्यापार समझौतों को लागू किया, साथ ही म्यांमार—थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान परियोजना और पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

जोड़ने वाले कई संपर्क प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया। सांस्कृतिक कूटनीति जैसे बौद्ध और रामायण पर केंद्रित आदान-प्रदान ने दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध और मजबूत किए हैं। सुरक्षा आयाम में भी भारत ने आसियान देशों के साथ सैन्य अभ्यास, नौसैनिक सहयोग, और रक्षा आपूर्ति को बढ़ावा दिया है, जिससे हिंद-प्रशांत में भारत की भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़े हैं।

नेबरहुड फ़र्स्ट नीति भारत की विदेश नीति का मूल स्तंभ है, जिसका उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों—नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान आदि के साथ विश्वासपूर्ण, स्थिर और समृद्ध संबंध बनाना है। 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद सार्क देशों के नेताओं को शपथग्रहण समारोह में आमंत्रित करना इस नीति की शुरुआती झलक थी। इस पहल के तहत भारत ने पड़ोसी देशों को अवसंरचना निर्माण, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, आपदा राहत और कनेक्टिविटी में प्राथमिकता दी है। उदाहरणस्वरूप, नेपाल और बांग्लादेश में सड़क-रेल परियोजनाएँ, श्रीलंका को आर्थिक संकट के समय 4 अरब डॉलर से अधिक की सहायता, मालदीव को तटीय सुरक्षा उपकरण, तथा सेशल्स-मॉरीशस में समुद्री रडार सिस्टम—ये सभी भारत की सक्रिय और जिम्मेदार पड़ोसी नीति को दर्शाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान “वैक्सीन मैत्री” पहल के तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देकर भारत ने क्षेत्रीय मानवीय नेतृत्व भी प्रदर्शित किया।

सागर (Security and Growth for All in the Region) पहल भारत की हिंद महासागर रणनीति का आधार है। 2015 में घोषित इस दृष्टिकोण में पाँच प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं — विश्वास एवं पारदर्शिता, समुद्री कानूनों का सम्मान, क्षेत्रीय हितों के प्रति संवेदनशीलता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। इस रणनीति के माध्यम से भारत स्वयं को हिंद महासागर में “नेट सिक्वोरिटी प्रोवाइडर” के रूप में स्थापित करना चाहता है। सागर के तहत भारत ने मॉरीशस, मालदीव, सेशल्स और श्रीलंका को गश्ती जहाज़, हेलीकॉप्टर, निगरानी विमान और कोस्ट-गार्ड प्रशिक्षण प्रदान किया है, साथ ही समुद्री रडार नेटवर्क स्थापित किए हैं। साझा नौसैनिक अभ्यासों और समुद्री आपदा राहत अभियानों के माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ समन्वय भी मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त, चाबहार बंदरगाह का विकास और हिंद-प्रशांत में सहयोग के लिए तैयार की गई आईओआरए और इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जैसी पहलें सागर सिद्धांत को और व्यापक बनाती हैं।^{xv}

समकालीन वैश्विक चुनौतियाँ और भारत की रणनीति: ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल डिप्लोमेसी भारत आज ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल डिप्लोमेसी जैसी उभरती चुनौतियों के बीच संतुलित व बहुआयामी रणनीति अपनाकर आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत जीवाश्म ईंधन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्रोतों में विविधता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सस्ते रूसी तेल का आयात बढ़ाकर अपनी लागत कम की, वहीं मध्य-पूर्व और अमेरिका के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को भी मजबूत किया। इसके समानांतर, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर रहा है—अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 नेट जीरो का लक्ष्य इसी का हिस्सा हैं। खाड़ी देशों के साथ हरित ऊर्जा सहयोग भी तेजी से बढ़ा है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव आया, जिसे भारत एक अवसर के रूप में उपयोग कर रहा है। "मेक इन इंडिया" और उत्पादन-प्रोत्साहन योजनाओं ने वैश्विक कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित किया है—ऐप्पल, सैमसंग और अन्य कंपनियों ने बड़े निवेश किए हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत अमेरिका, ताइवान आदि के साथ साझेदारी कर रहा है, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर स्थापित Supply Chain Resilience Initiative महत्वपूर्ण कच्चे माल और अर्धचालकों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास है। भारत-सऊदी-यूरोप के बीच प्रस्तावित इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर भी वैश्विक आपूर्ति शृंखला को नया विकल्प देने की दिशा में कदम है।¹

डिजिटल डिप्लोमेसी भारत की विदेश नीति का एक नया और प्रभावी स्तंभ बन गई है। आधार, न्यू, कोविन जैसे भारतीय डिजिटल मॉडल अब कई विकासशील देशों को आकर्षित कर रहे हैं, और भारत उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। भारत की यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जी20 के दौरान वैश्विक चर्चा का प्रमुख विषय बनी। साइबर सुरक्षा और इंटरनेट गवर्नेंस में भी भारत मानव-केंद्रित और बहुपक्षीय ढांचे की वकालत कर रहा है। भारत वैश्विक तकनीकी नियम बनाने में सक्रिय भूमिका चाहता है, ताकि 5G/6G, एआई और डेटा गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उसका प्रभाव बढ़े।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत संतुलित रुख अपनाए हुए है—वह स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए भी विकसित देशों से "जलवायु न्याय" और वित्तीय सहायता की मांग करता है। पंचामृत लक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-सहिष्णु अवसंरचना गठबंधन भारत की जलवायु नेतृत्व की मिसाल हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था में भारत खुलापन और संरक्षण—दोनों का संयोजन अपनाता है; जहाँ वह घरेलू हितों की रक्षा के लिए कुछ समझौतों से दूर रहता है, वहीं अन्य देशों से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा रहा है।

इन सभी पहलुओं में भारत निरंतर यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक दक्षिण की आवाज़ अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचे। कोविड वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा छूट, खाद्यान्न निर्यात नियमों में लचीलापन, विकास वित्त संस्थानों में बदलाव जैसी माँगों को भारत ने प्रमुखता दी है। "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ" शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर भारत ने विकासशील देशों के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका और दृढ़ की है।

निष्कर्ष

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने अपनी विदेश नीति को संतुलित, बहुआयामी और रणनीतिक रूप से लचीला बनाते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला है। गुटनिरपेक्षता की पारंपरिक सोच को 21वीं सदी की रणनीतिक स्वायत्तता में बदलते हुए भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ घनिष्टता बढ़ाई, रूस के साथ पुराने सहयोग को बनाए रखा और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय स्तर पर नेबरहुड फ़र्स्ट नीति के माध्यम से भारत अपने पड़ोस को स्थिर और सहयोगी बनाए रखने में निवेश कर रहा है, क्योंकि शांत पड़ोस उसकी वैश्विक आकांक्षाओं की नींव है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। जी20 की अध्यक्षता, ब्रिक्स और



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

क्वाड में संतुलनकारी रुख, और वैश्विक जलवायु वार्ताओं में सक्रिय सहभागिता भारत की उभरती प्रतिष्ठा को दर्शाती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का उसका दावा भी अधिक मजबूत हुआ है। चुनौतियाँ जैसे चीन के साथ सीमा तनाव, पाकिस्तान के साथ रिश्तों में जड़ता और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव अभी भी मौजूद हैं, पर भारत ने सिद्ध किया है कि वह जटिल परिस्थितियों में भी परिपक्व संतुलन साधने में सक्षम है। आज भारत पश्चिम और रूस, अरब देशों और इस्राइल, तथा अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाते हुए ब्रिक्स और एससीओ में भी सक्रिय रह सकता है। समग्र रूप से, 21वीं सदी के बहुध्रुवीय विश्व में भारत एक स्थिरता प्रदाता, विकास सहयोगी और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में उभर रहा है, और भविष्य में उसकी विदेश नीति और अधिक आत्मविश्वासी और पहलकारी होने की संभावना है।

संदर्भ सूची

- i Ministry of External Affairs, Government of India. *Suo-Moto Statement by External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar in the Rajya Sabha on the Situation in Ukraine*. (15 March 2022) mea.gov.in
- ii Renshaw & Verma. *India halves Russian oil imports, sources say no cuts seen*. (17 Oct 2025) - Russia now 36% of India's oil imports reuters.com.
- iii Ministry of External Affairs, Government of India. *Joint Statement on the Inaugural India-U.S. 2+2 Ministerial Dialogue*. (6 September 2018) mea.gov.in
- iv Bose N and Zengerle P. Biden, Modi hail new era for US-India ties and tout deals. (23 June 2023), <https://www.reuters.com/world/biden-modi-strengthen-ties-with-defense-trade-agreements-2023-06-22/#:~:text=Biden%20and%20Modi%20signed%20off,112>
- v Moore-Carrillo J and Harris B. US, India cement partnership with slew of new defense deals. (23 June 2023), <https://www.defensenews.com/congress/2023/06/23/us-india-cement-partnership-with-slew-of-new-defense-deals/#:~:text=Congress>
- vi Das & Miglani. *"India said ties with China could not be normal until troops pulled back..."* (26 March 2022) - India-China border standoff and Galwan casualties reuters.com.
- vii Chatham House. Back-to-back BRICS and Quad meetings highlight India's increasingly difficult balancing act. (13 August 2025), Accessed by: <https://www.chathamhouse.org/2025/07/back-back-brics-and-quad-meetings-highlight-indias-increasingly-difficult-balancing-act>
- viii Council Foreign Relations. What is the BRICS group and Why is it expanding? (26 June 2025), Accessed by: <https://www.cfr.org/backgrounder/what-brics-group-and-why-it-expanding#:~:text=What%20Is%20the%20BRICS%20Group,India%27s%20growing%20rivalry>
- ix Council Foreign Relations. US – India Relations-1947-2025, Accessed by: <https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations#:~:text=President%20Joe%20Biden%20hosts%20Prime,heightened%20regional%20tensions%20with%20China>



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

ISSN No: 3049-4176

-
- x Vasudev Kumtumbkam. G20 New Delhi Leaders' Declaration. (9-10 September 2023), Accessed by: <https://www.mea.gov.in/Images/CPV/G20-New-Delhi-Leaders-Declaration.pdf#:~:text=76,will%20significantly%20contribute%20to%20addressing>
- xi Jayasinghe U. India to support crisis-hit Sri Lanka's economic recovery. (June 2023), Accessed by: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/india-says-will-support-crisis-hit-sri-lankas-economic-recovery-2022-06-23/#:~:text=,the%20statement%20said>
- xii SASEC. India and Nepal Sign cross-border energy, trade and transit deals. (2 June 2023), Accessed by: <https://www.sasec.asia/index.php?page=news&nid=1510&url=india-nepal-sign-cross-border-energy-trade-transit#:~:text=Among%20the%20agreements%20signed%20were,in%20the%20next%2010%20years>
- xiii The Economic Times. India announces Rs 4,000 cr concessional credit line to fund energy projects in Bhutan. (11 November 2025), Accessed by: <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-announces-rs-4000-cr-concessional-credit-line-to-fund-energy-projects-in-bhutan/articleshow/125253915.cms?from=mdr>
- xiv Ministry of External Affairs. Upgradation of the Technical Mission of India in Kabul to Embassy of India. (21 October 2025), Accessed by: https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/40223/Upgradation_of_the_Technical_Mission_of_India_in_Kabul_to_Embassy_of_India#:~:text=In%20keeping%20with%20the%20decision,and%20aspirations%20of%20Afg%20han%20society
- xv https://en.wikipedia.org/wiki/Security_and_Growth_for_All_in_the_Region#:~:text=further%20east%20to%20the%20Indo,13